

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 870
गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान योजना के अंतर्गत वायुमार्ग

870. श्री के. गोपीनाथ:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उड़ान योजना के अंतर्गत उन वायुमार्गों का ब्यौरा क्या है जो निजी एयरलाइनों द्वारा उनके कार्यान्वयन के लिए धनराशि स्वीकृत होने के बावजूद अपर्याप्त/अनुपयुक्त बने हुए हैं और इस संबंध में अब तक स्वीकृत एवं उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त योजना के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है और प्रचालित वायुमार्गों के संदर्भ में अब तक कितनी प्रगति हुई है;
- (ग) उड़ान योजना के वायुमार्गों पर निजी एयरलाइनों के सामने आने वाली प्रचालन संबंधी चुनौतियों का मूल्यांकन करने के लिए कौन से तंत्र मौजूद हैं और उक्त चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) ऐसा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि यह योजना अल्पसेवित क्षेत्रों में समान रूप से हवाई संपर्क प्रदान करने के अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त कर सके और एयरलाइनों को केवल व्यावसायिक रूप से लाभदायक मार्गों को प्राथमिकता देने से रोका जा सके,?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले)

(क) : आरसीएस के अंतर्गत गैर-प्रचालित हवाईअड्डों और वहां से जाने वाले मार्गों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

(ख) सरकार ने दिनांक 21.10.2016 को 10 वर्षों की अवधि के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) शुरू की गई थी। दिनांक 15/07/2025 तक इस योजना के अंतर्गत 92 असेवित और अल्पसेवित हवाई अड्डों (15 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरोड्रोम सहित) को जोड़ने वाले 637 आरसीएस मार्ग आरंभ हो चुके हैं।

(ग) : परिचालन चुनौतियों की पहचान करने के लिए सरकार एयरलाइनों सहित सभी हितधारकों के साथ आवधिक समीक्षा करती है। इसमें विभिन्न परिचालन चुनौतियां शामिल हैं, जिनमें कुछ मार्गों पर यात्रियों की कम मांग, कुछ हवाईअड्डों पर कम दृश्यता, स्लॉट की उपलब्धता से संबंधित चुनौतियां, एटीसी निगरानी घंटे, हवाईअड्डों के विकास में देरी और विमानों की कमी शामिल हैं। इन मुद्दों पर काबू पाने के लिए सरकार विशेष दृश्यता उड़ान नियम (वीएफआर), उपकरण उड़ान नियम (आईएफआर) और अपेक्षित दिक्कालन निष्पादन (आरएनपी) प्रक्रियाओं जैसी प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपना रही है और हवाई अड्डों के साथ समन्वय कर रही है। हवाई अड्डों का समय पर विकास और प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित राज्य सरकारों से उच्च क्षमता वाले हवाईअड्डों की पहचान करने और उन्हें

प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, एयरलाइनों को मार्ग आवंटित करने से पहले, समय पर परिचालन के लिए व्यावसायिक योजनाएँ प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(घ) : आरसीएस-उड़ान एक बाजार-संचालित योजना है, जिसका उद्देश्य मांग-आधारित पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से देश के असेवित और अल्पसेवित हवाई अड्डों को संपर्क प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत केवल वे मार्ग ही आवंटित किए जाने के पात्र हैं जो किसी असेवित या अल्पसेवित एयरोड्रोम को जोड़ते हैं। न्यायसम्मत हवाई सम्पर्क सुनिश्चित करने के लिए, योजना यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी क्षेत्र या ऑपरेटर को असमान रूप से मार्ग आवंटित न किए जाएं।

अनुलग्नक

आरसीएस के तहत विकसित वर्तमान में गैर-प्रचालित हवाईअड्डों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	हवाईअड्डा	व्यय करोड़ों में	प्रचालित/पुनः आरंभ किए जाने वाले आरसीएस मार्ग	टिप्पणी
1.	अरुणाचल प्रदेश	पासीघाट	0.07	जोरहाट , शिलांग	
2.	गुजरात	भावनगर	69.18	पुणे	

3.	पंजाब	पठानकोट	5.18	शून्य	कोई भी अवार्ड किया गया मार्ग उपलब्ध नहीं है।
4.	राजस्थान	जैसलमेर	10.34	शून्य	
5.	सिक्किम	पाकयोंग	178.75	शून्य	
6.	उत्तर प्रदेश	कुशीनगर	108.22	सहारनपुर	कुशीनगर को सहारनपुर से जोड़ने वाला आरसीएस मार्ग स्पाइसजेट को क्यू400 टाईप के विमान के साथ अवार्ड किया गया।
7.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	31.94	लखनऊ , कानपुर, हिंडन	हवाई अड्डे पर चल रहे रनवे री-कार्पेटिंग कार्य के कारण लखनऊ से जुड़ने वाले सभी मार्ग निलंबित कर दिए गए हैं।
8.	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	29.57	लखनऊ	
9.	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	32.79	लखनऊ , कानपुर, प्रयागराज , वाराणसी, खजुराहो	
10.	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती	32.84	लखनऊ , कानपुर, प्रयागराज , वाराणसी	
11.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	30.41	लखनऊ , कानपुर, हिंडन , सहारनपुर, देहरादून	
